

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

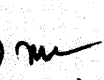
निगरानी प्रकरण क्रमांक 1673-दो/2008 - विरुद्ध- आदेश दिनांक  
10-10-2008 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर  
- प्रकरण क्रमांक 476/2006-07 निगरानी

- 1- कल्लू उर्फ कालीचरण पुत्र मोहन चमार
- 2- भज्जू पुत्र मोहन चमार लावल्द फोट  
निवासीगण ग्राम गोरा खास तहसील  
पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश  
विरुद्ध

---आवेदकगण

- 1- महेश पुत्र जयराम तिवारी
- 2- दिनेश पुत्र जयराम तिवारी
- 3- चिरोंजी पुत्र हरदास कुम्हार  
निवासीगण ग्राम गोरा खास तहसील  
पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
- 4- मध्य प्रदेश शासन

--अनावेकगण

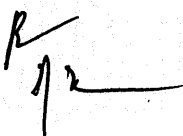
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एन.डी.सिंह)   
( अना.क्र. 1,2 की ओर से श्री कुँवर सिंह कुशवाह )  
( अना.क्र. 4 के पैनेल लायर श्री राजीव गौतम )  
( अना.क्र. 2 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय )

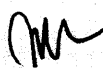
आ दे श

(आज दिनांक 15-2-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण  
क्रमांक 476/06-07अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-08  
के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत  
प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि तहसीलदार पृथ्वीपुर ने प्रकरण  
क्रमांक 25 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 14-4-2002 से






ग्राम गोरा खास में विभिन्न भूमिहीनों को भूमि का आवन्तन किया तहसीलदार पृथ्वीपुर के आदेश दिनांक 14-4-2002 से आवेदक क्रमांक-1 एवं 2 के हित में हुये भूमि सर्वे क्रमांक 494/1/1/3 रकबा 1.000 हैक्टर के सम्मिलित पट्टा तथा अनावेदक क्रमांक 3 के हित में भूमि सर्वे क्रमांक 494/1/1/1 रकबा 0.625 हैक्टर के पट्टे के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के समक्ष अपील क्रमांक 46/2015-16 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने आदेश दिनांक 15-9-2006 पारित करके आवेदकगण के हित में हुये पट्टे के साथ अनावेदक क्रमांक 3 को हुआ पट्टा भी निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 476/06-07 अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-08 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1, 2 के अभिभाषक, म०प्र०शासन के पैनल लायर के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक क्रमांक-1 एवं 2 को भूमि सर्वे क्रमांक 494/1/1/3 रकबा 1.000 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का सम्मिलित पट्टा अन्य पट्टाग्रहीताओं के साथ तहसीलदार पृथ्वीपुर ने प्रकरण क्रमांक 25 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 14-4-2002 से प्रदान किया है। आवेदकगण के अभिभाषक तर्क यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने पट्टा मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 का कब्जा है। विचार



योग्य है कि वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 का कब्जा रहा हो, किन्तु वादग्रस्त भूमि शासकीय थी, एवं शासकीय भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 का कब्जा होने से अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखल किया सकता है एवं पट्टाग्रहीताओं का अनुसूचित जाति संबर्ग का होने एवं के भूमिहीन के कारण मध्य प्रदेश शासन की वर्ष 1001-02 में भूमि आवंटन की विशेष योजना के अंतर्गत पट्टा देने में तहसीलदार ने भूल नहीं की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया है कि तहसीलदार पृथ्वीपुर के प्रकरण क्रमांक 25 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 14-4-2002 से आवेदकगण को पट्टा प्राप्त होने के बाद हलका पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक ने मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया है तथा कब्जा प्राप्ति से ही आवेदकगण ने वादग्रस्त भूमि को समतल करके तथा धन एवं श्रम लगाकर उन्नत कृषि योग्य बना लिया है आवेदक क्र-2 बेओलाद मरा है जिसका आवेदक क्रमांक 1 सगा भाई होने से विधिक वारिस है जो मौके पर काविज होकर खेती कर रहा है यदि आज की स्थिति में आवेदक से भूमि वापिस लेकर अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाता है, आवेदक को बाल-बच्चों के पालन में बहुत बड़ा व्यवधान हो जावेगा। यदि आवेदक के अभिभाषक के इन तर्कों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -

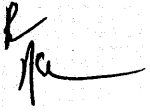
1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरुद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटित को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता।

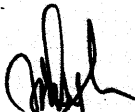
R  
/

(M)

उपरोक्त आधारों पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 14-4-2002 के बिरुद्ध दिनांक 30-1-2006 को अवधि-वाह्य प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 15-9-06 से स्वीकार करने में भूल की है एवं अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 476/06-07अ-19 निगरानी में आदेश दिनांक 10-10-08 पारित करते समय उक्त तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी का आदेश दिनांक 14-4-2002 एवं अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर का आदेश दिनांक 10-10-08 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 476/06-07अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-08 एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा अपील क्रमांक 46/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15-9-2006 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदकगण के हित तक तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 25 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 14-4-2002 यथावत् रखा जाता है।



  
(एम0के0सिंह)  
सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर